



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 621]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

संख्या 44/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 846(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “सभी प्रकार के व्यास वाले ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स” के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 फरवरी, 2015, जिसे सा.का.नि. 93 (अ) दिनांक 13 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपादन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/13/2018-डीजीएडी, दिनांक 04 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के, राजपत्र असाधारण, के भाग I, खंड 1 में दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठन में समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपादन शुल्क के मध्यावधि समीक्षा, जिसे अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 07/13/2018-डीजीएडी, दिनांक 08 अगस्त, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष रहा है कि :—

- (क) भारत में होने वाले कुल आयात में चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले विषयगत माल का आयात 2012 के 69% से कम हो करके पीओआई अर्थात् 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि में 55% हो गया है, जबकि अन्य देशों से होने वाला आयात 2012 के 31% से बढ़कर पीओआई के दौरान 45% हो गया है;
- (ख) कुल मिलाकर घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है। घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और विषयगत देश से होने वाले तथाकथित फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई सारवान क्षति नहीं हो रही है।
- (ग) भारत में इस विषयगत माल की बहुत कमी है और बढ़ते हुए आयात के साथ-साथ घरेलू मांग में होने वाली खास वृद्धि की तुलना में घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जिसके कारण घरेलू बाजार में इस विषयगत वस्तु की अत्यंत कमी हो गई है।
- (घ) प्राधिकारी के समक्ष आए मामले के तथ्यों से यह पता नहीं चलता है कि यदि प्रतिपाटन शुल्क को खत्म कर दिया जाए तो कोई भरमार की स्थिति या नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है;

और उनका यह निष्कर्ष है कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित “विषयगत वस्तु” के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 फरवरी, 2015 जिसे सा.का.नि. 93 (अ) दिनांक 13 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/74/2014-टीआरयू (पार्ट)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2018

**No. 44/2018-Customs (ADD)**

**G.S.R 846(E).**—Whereas, the designated authority *vide* notification number 7/13/2018-DGAD, dated the 4th April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th April, 2018, had initiated the Mid-term Review in term of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Graphite Electrodes of all diameters’ (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2015- Customs (ADD), dated the 13<sup>th</sup> February, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 93(E), dated the 13<sup>th</sup> February, 2015;

And whereas, in the matter of Mid-term Review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification number F. No. 7/13/2018-DGAD, dated the 8<sup>th</sup> August, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8<sup>th</sup> August, 2018, has come to the conclusion that:

- (a) the imports of the subject goods from subject country in total imports into India has declined from 69% in 2012 to 55% in period starting from 1<sup>st</sup> April, 2017 to 31<sup>st</sup> March, 2018 (POI) whereas the share of imports from other countries has increased from 31% in 2012 to 45% during the POI;
- (b) there is overall improvement in the health of the domestic industry. The domestic industry is not suffering from injury and the alleged dumped imports from the subject country are not resulting in material injury to the Domestic Industry;
- (c) there is an acute shortage of the subject goods in India and an insignificant increase in production capacities of the domestic producers compared to the significant rise in Indian demand combined with increased exports has led to a serious shortage of subject goods in the Indian market;
- (d) the facts of the case before the Authority do not indicate any likelihood of dumping and injury in case of cessation of AD duties;

and has concluded that continuance of anti-dumping duty is not warranted and has recommended discontinuance of existing anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 04/2015- Customs (ADD), dated the 13<sup>th</sup> February, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 93(E), dated the 13<sup>th</sup> February, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/ 74/2014-TRU (Pt)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.